

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बढकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2०25 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 1० और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियाँ, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 3०0 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (‘सॅड’) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए अनाज किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सोबेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक टवीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियों, जैसे चंबल और बतना, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। खतरनाक कचरा अधिकांशतः नदियों और जलाशयों में बहा दिया जाता है जो राजस्थान के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यहां जल संसाधनों की कमी के कारण लोग पहले से ही सीमित जल स्रोतों पर निर्भर हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सोबेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगमंगल झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सीलोज और औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मसबे का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकाना और राजमर्ग जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मलबा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अनुचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे धूल में जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, खर्ब रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सोबेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और बाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन प्रष्टाचाली और लापरवाही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रोसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिंतक

“वोकल फॉर लोकल” के आह्वान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.....



हेमन्त सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 19०5 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष

2०15 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसी ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अजरक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही

- ‘स्वदेशी’ से ‘आत्मनिर्भरता’ तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में ‘वोकल फॉर लोकल’ की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2०25’ लागू की है।

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से पनपती स्थानीय पहचान :- देश

का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान के सभी अंचलों में अलग-अलग परिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। राज्य सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में विशिष्ट एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर की खूबसूरत पीलू जाल (वानस्पतिक प्रजाति), प्रतापगढ़ के थेवा आभूषण (उत्पाद) की बेजोड़ कलाकृति, अनोखी महक से सराबोर बीकानेर की मेथी (उपज), सदियों पुरानी धरोहर की छवि को उकेरता नागीर का मीरा स्मारक (पर्यटन स्थल), सिरोही की उकूछ प्रतिभाओं के सामर्थ्य को दर्शाती तीरंदाजी

—हेमन्त सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ,

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

आज जब भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमें अपने संसाधनों, व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में वह क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा, जो अने वाले देशकों में देश को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाए। पेट्रोलियम सेक्टर इसकी सबसे अहम कड़ी है—और यह वही क्षेत्र है जहाँ बिखराव, विभिन्न ब्रांड, गुणवत्ता की खाइयों, डिस्ट्रिब्यूशन में उलझन और बार-बार सामने आती घण्टीय-चोरियों की खबरें आम हो चुकी हैं।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कितनी ही सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ देश में तेल की आपूर्ति का जिम्मा उठाती हैं। लेकिन क्या ये बिखराव और प्रतिस्पर्धा जनता को वाकई बेहतर सेवा दे पा रही है? हर कंपनी का अपनी कर्पांडीज, अलग-अलग बफर स्टॉक्स, अलग स्टोरेज-ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अपनी अपनी लॉबी, नेताओं-अफसरों की हिस्सेदारी, पुराना नियम-कायदा, और अंत में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में अंतर। क्या कभी आपने सोचा—एक शहर में दो ब्रांड के पंप पर, एक ही दिन एक ही पेट्रोल के दाम-गुणवत्ता अलग कैसे हो सकते हैं?

अब समस्या सिर्फ कीमत या उपभोक्ता के भ्रम की नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की लागत व पारदर्शिता की कमी की भी है। रोजमर्रा के अखबारों की हेडलाइन बनती “पेट्रोल डीजल चोरी”, काला बाजारी, टूक-टैकर घोटाले.. अभी ताजातरीन मामला एक अखबार की फ्रंट पेज पर, पाइप लाइन से क्रूड आयल चोरी को कई दशकों से चल रही है और एक बड़े माफिया का रूप ले चुकी है जो अपने आप में सिस्टम की जाहिरात है। मर्जर से क्या-क्या बदल सकता है?

राशिफल गुरुवार 7 अगस्त, 2025



पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2०82, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन 2:०1 तक, विक्कुम्भ योग प्रातः 6:42 तक, तैतिल करण दिन 2:28 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:11 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रविवोग दिन 2:०1 से आरम्भ होगा। आज आखेटक त्रयोदशी और शिव पवित्रारोपण है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 1०:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:5० तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:3० से 3:०0 तक। सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:०7

का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां—भारत को सीखना होगा।

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियां (59० अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक-चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आगे बढ़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:—

सऊदी अरामको (Saudi Aramco)

वार्थिक राजस्व: लगभग 59० अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैपिटलाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन

अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical)

वार्थिक राजस्व: लगभग 487 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina)

वार्थिक राजस्व: लगभग 486 अरब

अमेरिकी डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC)

वार्थिक राजस्व: लगभग 365 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 2०2 अरब अमेरिकी

डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास

13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है,

इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार

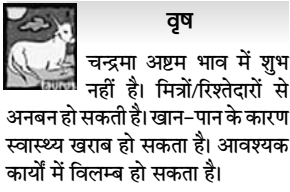
पूंजीकरण 2,०9,०65 करोड़ रुपये है और

इसके पास कुल रिजर्व्स 1,72,716 करोड़

रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर

भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री

7,58,1०6 करोड़ रुपये तक पहुंचती है।

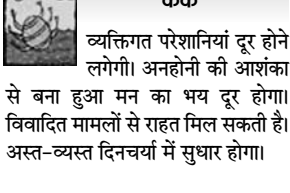


चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ बनी रहेगी। मित्रों/रिश्तेदारों से

अनवन हो सकती है। खान-पान के कारण

स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आवश्यक

कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने

लगेगी। अनहोनी की आशंका

से बचा हुआ मन का भय दूर होगा।

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज

किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273

करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का

मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और

रिजर्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक

शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएम ने

4,4०,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और

13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास

2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी

पूंजीकरण और 49,०16 करोड़

रिजर्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका

शेयर 425 है। बिक्री 4,34,1०6

करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ

6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल

इक्विटी पूंजी 2०,173 करोड़ रुपये, कुल

मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और

कुल रिजर्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो

जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484

करोड़ रुपये और मिलाजुला शुद्ध लाभ

33,862 करोड़ रुपये तक पहुंचता है।—

यदि इंडियन ऑयल, भारत

पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी

कंपनी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम

संघनियों में मर्ज करे एक “मेगा इंडिया

पेट्रोलियम” कंपनी का रूप लेती है, तो

उसके संभावित फायदे और वैश्विक

प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:—

भारत की ‘मेगा कंपनी’ का संयुक्त

वार्थिक राजस्व लगभग 2०0–25० अरब

अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है,

जिससे वह दुनिया की टॉप-5 तेल कंपनियों

की कतार में आ सकती है।

बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी

बढ़कर लगभग 200–3०० अरब अमेरिकी

डॉलर के लगभग पहुंच सकती है, जिससे

भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनता को पूरे देश में एक ही दर और